Tc.No. : GUJHIN00722

पेज: 4, मुल्य 1 रु.

क्रांति समय

संस्थापक / संपादक : सुरेश मौर्या

E-mail: krantisamay@gmail.com, www.krantisamay.com

वर्ष: 1 अंक: 40 , 03 नवम्बर, शुक्रवार 2017, सूरत, हिन्दी दैनिक मो. 9879141480

4 ओ ब्लॉक आगम नवकार कॉम्पलेक्ष, सचीन रेल्वे स्टेशन के पास, सूरत-गुजरात

सार समाचार

आपके पास है दो रुपए का सिक्का तो लखपति बन सकते हैं आप!

नई दिल्ली। आप विश्वास नहीं करेंगे पर एक दो रुपए का सिक्का आपको लखपति बना सकता है। दरअसल कुछ दिनों पहले ही हैदराबाद में एक पुराने 2 रुपए के सिक्के की नीलामी की गई, जिसमें खरीदने वाले से उसे तीन लाख रुपए में खरीदा। हैदराबाद आर्ट गैलरी के बाहर नीलामी में एक आदमी रातों-रात अमीर बन गया। 1980 के दशक के सिक्के अमीरों के बीच बहुत लोकप्रिय रहे हैं जिसमें मुंबई टकसालों के सिक्के देश में बहुत लोकप्रिय हैं। इन सिक्कों में डायमंड का निशान बना होता है। यदि आपके पास ऐसे निशान वाले सिक्के हैं, तो आप भी लखपति बन सकते है।

बदायूं: दुष्कर्म का विरोध करने पर विधवा भाभी को जिंदा जलाया

बदायूं। बदायूं जिले के इस्लामनगर में दुष्कर्म का विरोध करने पर एक व्यक्ति ने अपनी विधवा भाभी को कथित रूप से जिंदा जला डाला। पुलिस अधीक्षक (देहात) सुरेन्द प्रताप सिंह ने आज यहां दर्ज रिपोर्ट के हवाले से बताया कि इस्लामनगर थाना क्षेत्र के लभारी की मढ़ैया गांव में विधवा महिला नीलम (27) पर उसका देवर जितेन्द्र बुरी नजर रखता था। आरोप है कि जब नीलम उसका विरोध करती थी तो जितेन्द्र उसके साथ मारपीट करता था। उन्होंने बताया कि कल रात जितेन्द्र ने नीलम को र मे अकेला पाकर उसके साथ दुष्कर्म का प्रयास किया। नीलम ने विरोधस्वरूप शोर मचाया जिससे नाराज जितेन्द्र ने उसपर मिटटी का तेल छिड़ककर आग लगा दी। बुरी तरह से झुलसी नीलम की मौके पर ही मौत हो गई। नीलम के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी देवर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसकी तलाश शुरू कर दी है।

साइकिल रिक्शा की जगह ई-रिक्शा लाया जाए

समिति ने की सिफारिश

ई रिक्शा चलाने के लिए परिवहन विभाग ने तैयार की नई पालिसी

नई दिल्ली। बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा होंगे जब्त राजधानी में कुल कितनी ई रिक्शा चलाने की अनुमति हो, विभाग करे निर्णय चार लोगों के लिए बनी ई रिक्शा की जगह एक मीटर लंबाई की ई रिक्शा चलाने की तैयारीदो लोगों को बिठा सकेगी नई रिक्शा लेकिन पर्यावरण के मापदंड पर होगी अनुकूल दिल्ली सरकार की एक समिति ने राष्ट्रीय राजधानी में साइकिल रिक्शा को पूरी तरह हटाकर उसकी जगह पर्यावरण अनुकूल ई-रिक्शा लाने की सिफारिश की है। ई रिक्शा परिचालन को सुव्यवस्थित करने के लिए परिवहन विभाग की एक्सपर्ट टीम ने नया मसौदा तैयार किया है। अब बिना रजिस्ट्रेशन वाले ई रिक्शा को जब्त किया जाएगा। समिति ने अपनी रिपोर्ट में ई-रिक्शा की संख्या सीमा तय करने एवं रिक्शा मालिकों को स्थायी डाइविंग लाइसेंस देने के बाद ही वाहन का पंजीकरण करने की भी सिफारिश की। हाईकोर्ट के एक आदेश के बाद ई-रिक्शा को लेकर एक व्यापक नीति तैयार करने के लिए इस साल जनवरी में समिति गठित की गई। समिति की रिपोर्ट में कहा गया कि साइकिल रिक्शा की जगह पूरी तरह छोटे ई-रिक्शे लाए जाएं और इन वाहनों को ज्यादा पर्यावरण एवं जन अनुकूल बनाने के लिए कोशिशें की जाएं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत ई-रिक्शा की अधिकतम चौड़ाई एक मीटर और अधिकतम लंबाई 2.8 मीटर है और उसमें चार यात्रियों को बैठाने की मंजूरी है। समिति ने इससे छोटा ई-रिक्शा डिजाइन करने की सिफारिश की जिसमें केवल दो यात्री बैठ सकें।राजधानी में महिला सुरक्षा को ध्यान में रखकर एक्सपर्ट कमेटी ने प्रत्येक ई रिक्शा चालक को परिवहन विभाग से अधिकृत बैज लगाने आवश्यक करने की सलाह दी है ताकि अनधिकृत तौर पर असामाजिक तत्वों द्वारा यह रिक्शा न चलाया जाए। साथ ही लर्निंग लाइसेंसधारी को ई रिक्शा खरीदने की अनुमति न दी जाए बल्कि सिर्फ नियमित लाइसेंस धारक को ही खरीदने की अनुमति दी जानी चाहिए। समिति ने परिवहन विभाग को सुझाव दिया है कि बिना परिवहन विभाग से लाइसेंस प्राप्त किए ई रिक्शा बेचने वाली कंपनी को सील कर दिया जाए। साथ ही ई रिक्शा बेचने के लिए नई कंपनियों को अधिकृत किया जाना चाहिए ताकि वर्तमान मार्केट में एकाधिकार रखने वाली कंपनी का अधिपत्य समाप्त किया जा सके। जहां भी गाड़ियों के आने जाने की जगह हो वहां इन्हें खड़ा करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। ई रिक्शा के खराब बैटरी को प्रदूषण नियमों के अनुसार कचरा निष्पादन तरीके से समाप्त किया जाना चाहिए।

एनटीपीसी हादसाः

ऐसे झुलसे कि सिसकियां भी न भर पाए...5 घंटे छटपटाते रहे

रायबरेली। एनटीपीसी में बॉयलर फटने से झुलसे मजदूर पूरी तरह से स्याह हो गए। चमड़ी उधड़ गई।

ऐसे में ये मजदूर सिसकियां भी नहीं भर पा रहे।

रात करीब पौने नौ बजे जब रायबरेली से गया बिहार का झुलसा मजदूर चंदन सिविल अस्पताल पहुंचा तो उसे देख हर किसी की रुह कांप उठी। इसके बाद एक-एक करके आठ झुलसे मजदूर सिविल अस्पताल पहुंचे, उनका भी यही हाल था। देर रात उपमुख्यमंत्री केशव मौर्या, गृह विभाग के प्रमुख सचिव अरविंद कुमार घायलों को देखने के लिए अस्पताल पहुंचे।

रोंगटे खड़े हुए

सिविल अस्पताल की इमरजेंसी में सबसे पहले बिहार निवासी चन्दन कुमार को लाया गया। चन्दन का पूरा शरीर झुलस चुका है। इसके बाद ऊंचाहार निवासी वीरेंद्र, शंभु यादव, अरविंद, अजय मेहता, रामरतन, पियुष और नागेश को सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया। एक साथ मरीजों के आने से अस्पताल की इमरजेंसी में अफरा-तफरी मच गई।

चारों तरफ से चीख-पुकार मच गई। मरीजों की दर्द भरी करार सुनकर रोंगटे खड़े हो जा रहे थे। पूरी कोशिश करने के बावजूद इलाज में लगे डॉक्टर व नर्स बेबस दिख रहे थे।

साढ़े पांच घंटे छटपताते रहे घायल

एनटीपीसी में करीब साढ़े तीन बजे बॉयलर फट गया था। इसमें काम कर रहे काफी लोग जख्मी हो गए। घटना के बाद से आग में झुलसे लोगों को लखनऊ लाने का सिलसिला शुरू हुआ। करीब साढ़े पांच घंटे तक मरीजों को कोई इलाज नहीं मिला।

102 व 108 एम्बुलेंस से मरीजों को लाया गया। इस दौरान मामूली इलाज ही एम्बुलेंस में मिल पाया। पुख्ता इलाज न मिल पाने की वजह से मरीज छटपाते रहे। दर्द से कराह रहे मरीजों को सिविल समेत दूसरे अस्पतालों में भर्ती कराया गया।

ऊंचाहार एनटीपीसी हादसा : तोप के गोले से अधिक प्रेशर से फटा बॉयलर

काम मिलते ही हादसे का शिकार बना अमृतलाल

ऊंचाहार स्थित फरीदाबाद के अमृतलाल को क्या पता था कि एनटीपीसी में वह हादसे का शिकार बन जाएंगे। पत्नी समेत चार बच्चों की परवरिश के लिए वह बुधवार को पहले दिन ही काम करने गया था। इसके लिए ठेकेदार की ओर से कई तरह के वादे किए गए थे।

इसके चलते वह काम पर गया लेकिन हादसे का शिकार हो गया। जिस वक्त एनटीपीसी में हादसा हुआ उस वक्त अमृत की पत्नी सुनीता देवी बेटे आशीष के संग

खेत में धान काट रही थी। सुनीता के मुताबिक घटना की सूचना जैसे ही गांव पहुंची कोहराम मच गया। हर कोई भागो-भागो, बचाओ-बचाओ की गुहार लगाते हुए घटना स्थल की ओर से दौड़ पड़ा।

सिविल अस्पताल के चिकित्सक डॉ. आशुतोष दुबे ने कहा, एनटीपीसी से लाए गए मरीजों की हालत बेहद नाजुक है। सात मरीज तो सौ फीसदी तक झुलसे हैं। डॉक्टरों की टीम मरीजों को बचाने की कोशिश में जुटी है।

चुनाव विवाद में सीतामढ़ी के सांसद को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीतामढ़ी संसदीय सीट पर हुए चुनावों में उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने के मामले में दायर याचिका पर सांसद रामकुमार शर्मा और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने ये नोटिस उम्मीदवार रहे रामनिरंजन राय की अपील पर जारी किए हैं।बिहार पुलिस के अधिकारी रहे राय का नामांकन यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि वह पुलिस सेवा में हैं क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। राय ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में स्वीकार्यता का प्रश्न नहीं है इसे तीन माह की अवधि बीतने के बाद स्वत: स्वीकार मान लिया जाता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया हुआ है। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन

खारिज कर दिया। बाद में सरकार ने 16 फरवरी 2016 को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली। राय ने राष्ट्रवादी चेतना पार्टी की ओर से सीतामढ़ी सीट से चुनाव के लिए नामांकन भरा था

राय ने कहा कि उन्होंने मई 2014 में हुए संसदीय चुनावों से काफी पहले 31 दिसंबर 2013 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सरकार को नोटिस दिया था। लेकिन सरकार ने तीन माह की अवधि बीतने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अंतत: उन्होंने एसपी के पद से 1 अप्रैल 2014 को इस्तीफा दे दिया लेकिन सरकार ने उसे भी स्वीकार नहीं किया।

यह मामला वह पटना हाईकोर्ट ले गए थे। हाईकोर्ट ने फैसले में माना कि निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन गलत तरीके से खारिज किया था। निमयानुसार उन्हें सेवा से इस्तीफा देने का सबूत लाने के लिए दो दिन का समय देना चाहिए था। लेकिन फिर भी यह चुनाव को निरस्त करने का पर्याप्त कारण नहीं है।

इस मंदिर में सिर्फ महिलाओं को घुसने की इजाजत, मर्दों को प्रवेश के लिए करने पड़ते हैं ये काम...

नई दिल्ली। आपने शयद कभी नहीं सुना होगा कि भारत में एक ऐसा मंदिर भी है जो सिर्फ महिलाओं के लिए है और इसमें प्रवेश के लिए पुरुष प्रतिबंधित हैं। केरल के कोल्लम जिले में स्थित श्री कोत्तानकुलांगरा देवी मंदिर पूरे देश में इसलिए मशहूर है क्योंकि यहां पुरुषों का आना मना है। अगर पुरुषों को इस मंदिर में जाना है

महिलाओं की तरह श्रंगार भी करना पड़ता है

मंदिर की इस प्रथा की खास बात ये है कि पुरुषों को प्रवेश के लिए सिर्फ ड्रेस पहनना ही नहीं उन्हें महिलाओं की तरह सजना-संवनरा भी पड़ता है। श्री कोत्तानकुलांगरा देवी मंदिर में हर साल चाम्याविलक्कू त्योहार मनाया जाता है। इस त्योहार का हिस्सा बनने के लिए पुरुषों को मंदिर में ही मेक-अप का पूरा सामान मिल जाता है। यहां उनके तैयार होने के लिए साड़ी, गहने और मेकअप के लिए गजरा तक रखा होता है। जब तक पुरुष यह 16 श्रंगार न करलें

गर्भगृह के ऊपर छत और कलश नहीं

इस मंदिर एक खास बात ये भी है कि इसमें बाकी सभी मंदिरों की तरह इसके गर्भगृह के ऊपर कोई छत और कलश नहीं है।

पुलिस ने छापा मार पकड़ा

रैंक में छोटे अधिकारी की बीवी से अफेयर रखना एक कर्नल को पड़ा भारी,

नई दिल्ली। बठिंडा में एक कार्यरत कर्नल को अपने से कम रैंक वाले लेफ्टिनेंट की पत्नी के साथ अफेयर रखना भारी पड़ गया। मिलिटरी पुलिस ने कर्नल को उसके अधीनस्थ की वाइफ के साथ पकड़ने के बाद उनके खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। बता दें दोनों ही ऑफिसर्स इंजीनियर कोर से हैं।

सूत्रों के मुताबिक, मिलिटरी पुलिस ने लेफ्टीनेंट कर्नल के खिलाफ उनके कहने पर रात के तीन बजे छापा मारा। इससे मालूम होता है कि लेफ्टीनेंट कर्नल को मालूम था कि क्या होने वाला है। आपको बता दें कि आर्मी एक्ट के तहत, 'अपने साथ के अधिकारी की पत्नी से ऐसा व्यवहार रखना एक गंभीर अपराध माना जाता है। ऊपर से कर्नल का अपनी गलती मानना उन्हें 5 साल के लिए सजा भी दिला सकता है। बता दें कि कर्नल भटिंडा जोन का चीफ इंजीनियर है और जब यह छापा मारा गया तब लेफ्टिनेंट कर्नल गोल्फ टूर्नामेंट खेलने चंडीगढ से बाहर गया था।

कर्नल और लेफ्टीनेंट कर्नल की पत्नी ने बाद में भटिंडा की मिलिटरी हॉस्पीटल में चेकअप कराया।

आर्मी अपनी रैंकों के भीतर अतिरिक्त-वैवाहिक मामलों का उदय और ऐसे अपराधों के लिए दोषी पाए जाने वाले लोगों को गंभीरता से ले रही है।

यह केस उस केस के एक हफ्ते बाद आया है जब एक लेफ्टीनेंट कर्नल को अपने कॉलेज के दोस्त की बेटी से अफेयर रखने पर सस्पेंड कर दिया गया था। कर्नल को बाद में अनुचित व्यवहार ना रखने पर नौकरी से भी निकाल दिया गया था।

मानवाधिकार आयोग ने यूपी सरकार को जारी किया नोटिस, 6 सप्ताह में मांगा जवाब

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रायबरेली में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र में हुए हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह में जवाब मांगा आयोग ने रायबरेली के ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी के बिजली संयंत्र का बॉयलर फटने से कम से कम 28 लोगों की मौत की मीडिया रपटों का स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव के जरिये राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के अंदर विस्तत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए माना है कि यह जीने के अधिकार से जुड़ा मामला है और इसकी फौरन उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये, ताकि यह पता लग सके कि क्या इसके पीछे किसी तरह की लापरवाही या गलती थी। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं कि वह इस हादसे के प्रभावित लोगों को अविलम्ब सहायता मुहैया कराये। मालूम हो कि ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी के 500 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का बॉयलर कल शाम फ

ट जाने से भारी तबाही हुई थी। इस हादसे में अब तक 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) की टीम अब भी दुर्टनास्थल पर खोजबीन कर रही है। माना जा रहा है कि मलबे में अभी कुछ और शव दबे हो सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने बताया कि एनटीपीसी इस हादसे में मारे गये लोगों के परिजन को 20-20 लाख रुपये, गम्भीर रूप से घायल लोगों को 10-10 लाख तथा मामूली रूप से जख्मी लोगों को दो-दो लाख रुपये दिये जायेंगे। उन्होंने बताया कि टना की जांच के लिये केन्द्र ने एनटीपीसी के अधिशासी निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की है, जो 30 दिन में रिपोर्ट देगी।

खतरे की घंटी: चीनी किट बता रही है लड़का होगा या लड़की

लखनऊ। अब लिंग की जांच सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही नहीं हो रही है। खून की जांच से भी लिंग का पता लगाया जा रहा है। चीन की प्रतिबंधित किट से भारत में लिंग की जांच का खेल चल रहा है। गुपचुप तरीके से चीनी किट भारत में खपाई जा रही है। हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में किट पकड़ी गई हैं।

अप्रैल 2017 में हरियाणा और मुंबई समेत दूसरे राज्यों में चीनी किट से गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करने का घिनौना खेल चल रहा है।

अकेले हरियाणा में गर्भस्थ का लिंग पता करने के 80 मामले प्रकाश में आ चुके हैं। 10 से ज्यादा लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो चुकी हैं। इंडियन फेडरेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड इन मेडिसिन एंड बायोलॉजी (आईएफम्यूएमबी) के सदस्य डॉ. अतुल कुमार अग्रवाल ने बताया कि चीन से आयतित किट से न सिर्फ लिंग निर्धारण हो रहा है बल्कि गर्भ का चिकित्सीय समापन भी हो रहा है। उन्होंने बताया कि गर्भस्थ के खून के नमूने से उसके लिंग का पता लगाया जा रहा है। खून की दो बूंद किट पर रखी जाती है। नतीजा सामने आ जाता है।

चिकित्सा विज्ञान में इसे फिटल हीमोग्लोबिन जांच कहते हैं। इसके अलावा किट के साथ मुहैया कराई जा रही दवा से कोख में ही लड़कियों की हत्या किए जाने की भी आशंका है। उन्होंने बताया वे खुद भी हरियाणा सरकार और वहां के स्वास्थ्य महानिदेशक को भी पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि पत्र में प्रतिबंधित चीनी किट की बेच-खरीद पर कड़ाई से प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है।

निगरानी तंत्र कमजोर

आईएफ यूएमबी के डॉ. पीके श्रीवास्तव ने कहा कि प्रतिबंधित चीनी किट की बेच-खरीद की निगरानी व जांच तंत्र का पता लगाना कठिन है। पर, भारत में इस तरह की किट मिलना गंभीर बात है। इसकी धरपकड़ को लेकर अफसरों को अलर्ट हो जाना चाहिए, ताकि कोख में लड़कियों की हत्या को प्रभावी तरीके से रोका जा सके।

एके जैन, ड्रग कंट्रोलर, यूपी का बयान -

अभी प्रदेश में इस तरह की किट की बेच खरीद संबंधी कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। मामला गंभीर है। गर्भास्थ के लिंग का पता लगाना कानून अपराध है।

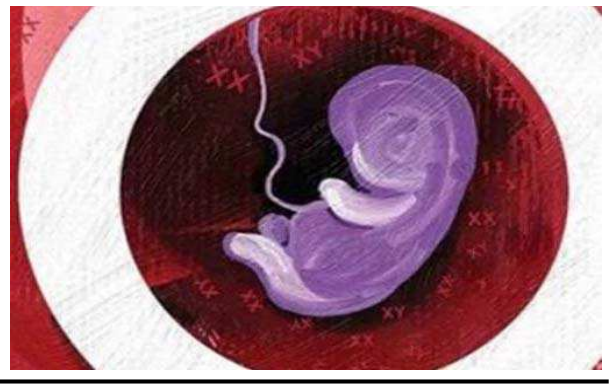

साधु को दिन में देखना, रात में देखना और
तब साधु पर विश्वास करना -रामकृष्ण परमहंस

देश की बड़ी उपलब्धि

कारोबार के लिए स्थिति सुगम बनाने वाले देशों की सूची में भारत का 100वें स्थान पर आना निश्चय ही देश की बड़ी उपलब्धि है। पिछले साल यह 189 देशों की सूची में 130 वें स्थान पर था। आज तक कभी भारत ने एक साथ इतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई थी। इस नाते यह ऐतिहासिक है। ध्यान रखिए यह रिपोर्ट जून तक के तयों पर आधारित है और इसमें 1 जुलाई से लागू जीएसटी शामिल नहीं है। जाहिर है, जब जीएसटी शामिल हो जाएगा तो भारत की रैंकिंग और सुधरेगी। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने देश को ऊपर के 50 देशों में लाने का जो लक्ष्य निर्धारित किया है, उसकी ओर हम बढ़ गए हैं। विश्व बैंक अपनी सूची में 10 मापदंडों पर देशों की रैंकिंग करता है। विश्व बैंक की वार्षिक रिपोर्ट ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2018 रिफार्मिंग टू क्रिएट जॉब्स' के ज्यादार मापदंडों में भारत ने अच्छा किया है। उदाहरण के लिए कराधान के मामले में भारत 53 स्थान की छलांग लगाकर 119 वें स्थान पर पहुंच गया। शोधन क्षमता समाधान एवं दिवाला कानून के सरकार के कदम से इस मापदंड पर भी भारत 136वें स्थान से 103वें स्थान पर पहुंचा है। छोटे निवेशकों के हितों की रक्षा, वित्त की उपलब्धता मामले में भारत दुनिया में शीर्ष 30 देशों में शामिल है। वह पिछले साल के 13वें स्थान के मुकाबले चौथे स्थान पर पहुंच गया है। वित्त की उपलब्धता के मामले में रैंकिंग 44वें से सुधरकर 29वें पर पहुंच गई। अनुबंधों को लागू करने के मामले में भारत की रैंकिंग 172 से सुधरकर 164 पर पहुंच गई। इस तरह की रैंकिंग का मतलब है कि प्रधानमंत्री ने केंद्र सरकार के सभी संबंधित अधिकारियों, प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से प्रथम 50 की सूची में आने का लक्ष्य बनाकर निश्चित समयावधि में कुछ चिह्नित सुधारों पर आगे बढ़ने का जो मंत्र दिया, उस पर काम हुआ है। इसके परिणामस्वरूप अब विदेशी निवेशक भारत की ओर ज्यादा तेजी से आकर्षित हो सकेंगे। भारत के बारे में यह आम धारणा बना दी गई थी कि यहां व्यापार कानून एवं प्रक्रियाएं काफी जटिल हैं, लालफीताशाही अभी भी है, कोई लाइसेंस हासिल करने में काफी समय लगता है और करों का ढांचा बेहद आपत्तिजनक है। जाहिर है, वर्तमान रैंकिंग इन धारणाओं को काफी हद तक तोड़ने वाली है। हालांकि अभी भी ऐसे क्षेत्र हैं, जिनमें काफी काम करने की आवश्यकता है। किंतु एक बार अच्छी शुरुआत हो गई तो आगे हम और अच्छे की ही उम्मीद करेंगे।

दागियों की भरमार

जनप्रतिनिधियों के आचरण को लेकर सालों से बहस होती रही है। लेकिन हालात में आंशिक सुधार ही हो पाया है। अभी भी संसद और विधान सभाओं में दागियों की भरमार है। एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक 4852 सांसदों और विधायकों में से 1581 के खिलाफआपराधिक मामले हैं। 543 लोक सभा सांसदों में से 184 यानी 34 फीसद के खिलाफआपराधिक मामले दर्ज हैं। वहीं, 231 राज्य सभा सांसदों में से 44 यानी 19 फीसद पर भी कई तरह के केस दर्ज हैं। यहां तक कि 4078 विधायकों में से 1353 (33 फीसद) के खिलाफ विभिन्न आपराधिक मामले दर्ज हैं। कह सकते हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। आपराधिक मामलों में दोषी नेताओं के चुनाव लड़ने पर आजीवन पाबंदी की मांग से जुड़ी याचिका पर सुनवाई के बाद एक बार फिर से चुनाव सुधार और स्वच्छ और बेदाग राजनीति का मसला ज्वलंत हुआ है। दरअसल, आपराधिक मामले 20-20 साल तक चलते रहने पर सुप्रीम कोर्ट ने भारी नाराजगी जाहिर की है। कोर्ट का सख्त और कड़क रुख इसी बात से समझा जा सकता है कि उसने इस मामले पर चुनाव आयोग के ठंडे रिस्पांस पर जमकर फटकार लगाई है। यही वजह है कि अदालत ने यह जानना चाहा कि कितने नेताओं पर आपराधिक मामले लंबित हैं? नेताओं को दोषी करार देने की दर क्या है? और नेताओं के खिलाफ एक साल में ट्रायल पूरा करने संबंधी आदेश पर कितना अमल हुआ? याचिका में मांग की गई है कि लंबित केस का निपटारा एक साल के भीतर हो और इसके लिए फास्ट ट्रैक अदालत का गठन हो। सुप्रीम कोर्ट ने इससे राजी होते हुए स्पेशल कोर्ट बनाने का ऑर्डर दे दिया, जो फास्ट ट्रैक कोर्ट की तर्ज पर काम करेगा। इससे पहले भी शीर्ष अदालत ने चुनाव आयोग को इस बात पर डांट पिलाई थी कि दागियों के मामले में उसका नजरिया स्वतंत्र नहीं है। राजनीति में धनबल और बाहुबल का प्रभुत्व है। इलेक्शन कमीशन ने आपराधिक संलिप्तता में चुनाव लड़ने पर आजीवन रोक लगाने का पक्षलिया। बात सही भी है कि जब आपराधिक मामले में दोषी ठहराए जाने पर नौकरशाह आजीवन नौकरी से बर्खास्त हो सकता है तो नेताओं पर छह साल की पाबंदी क्यों? सम्यक सुधार की दिशा में कुछ कदम बढ़ाने ही होंगे।

सत्संग

कर्मफल

भारतीय संस्कृति सबके लिए सभी भांति विकास का अवसर देती है। यह अति उदार संस्कृति है। विश्व में अन्य कोई धर्म संस्कृति में ऐसा प्रावधान नहीं है। उनमें एक ही इष्टदेव और एक ही तरह के नियम को मानने की परम्परा है। इसका उल्लंघन कोई नहीं कर सकता। अगर करता है तो दण्डनीय होगा। एक उद्यान में कई तरह के पौधे और फूल उगते हैं। इस भिन्नता से बगीचे की शोभा ही बढ़ती है। यही बात विचार उद्यान के संदर्भ में स्वीकार की जा सकती है। इसमें अनेक प्रयोग परीक्षणों के लिए गुंजाइश रहती है और सत्य को सीमाबद्ध कर देने से उत्पन्न अवरोध की हानि नहीं उठानी पड़ती। इस दृष्टिकोण के कारण नास्तिकवादी लोगों के लिए भी भारतीय संस्कृति के अंग बने रहने की छूट है, जबकि उनके लिए धर्मो के द्वार बंद हैं। भारतीय संस्कृति की दूसरी विशेषता है-कर्मफल की मान्यता। पुनर्जन्म के सिद्धांत में जीवन को अवांछनीय माना गया है और मरण की उपमा वस्त्र परिवर्तन से दी गई है। कर्मफल की मान्यता नैतिकता और सामाजिकता की रक्षा के लिए नितांत आवश्यक है। मनुष्य की चतुरता अद्भुत है। वह सामाजिक विरोध और राजदंड से बचने के अनेक हथकंडे अपनाकर कुकर्मरत रह सकता है। ऐसी दशा में किसी सर्वज्ञ सर्व समर्थ सत्ता की कर्मफल व्यवस्था का अंकुश ही उसे सदाचरण की मर्यादा में बांधे रह सकता है। परलोक की, स्वर्ग नरक की, पुनर्जन्म की मान्यता यह समझाती है कि आज नहीं तो कल, इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में कर्म का फल भोगना पड़ेगा। दुष्कर्म का लाभ उठाने वाले यह न सोचें कि उनकी चतुरता सदा काम देती रहेगी और वे पाप के आधार पर लाभान्वित होते रहेंगे। इसी प्रकार, जिन्हें सत्कर्मो के सत्परिणाम नहीं मिल सके हैं; उन्हें भी निराश होने की आवश्यकता नहीं है। अगले दिनों वे भी अदृश्य व्यवस्था के आधार पर मिल कर रहेंगे। संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण कर्म समयानुसार फल देते रहते हैं। इस मान्यता को अपनाने वाला न तो निर्भय होकर दुष्कर्मो पर उतारू हो सकता है और न सत्कर्मो की उपलब्धियों से निराश बन सकता है। अन्य धर्म जहां अमुक मत का अवलम्बन अथवा अमुक प्रथा प्रक्रिया अपना लेने मात्र से ईर की प्रसन्नता और अनुग्रह की बात कहते हैं, वहां भारतीय धर्म में कर्मफल की मान्यता को प्रधानता दी गई है और दुष्कर्मो का प्रायश्चित करके क्षति पूर्ति करने को कहा गया है।

''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस'

विश्व बैंक के आसान कारोबार के 10 मापदंडों में से छह पर भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। छोटे शेयरधारकों की सुरक्षा के मामले में भारत दुनियाभर में शीर्ष पांच देशों में शामिल है। इसी तरह, आसानी से कर्ज प्राप्त करने और बिजली कनेक्शन मिलने के मामले में भारत दुनिया के 30 शीर्ष देशों में शामिल है। कहा गया है कि भारत में अब नया बिजनेस शुरू करने में सिर्फ 30 दिन लगते हैं, जबकि 15 साल पहले 127 दिन लगते थे। विश्व बैंक 15 साल से यह रैंकिंग कर रहा है। अभी तक जॉर्जिया और रवांडा जैसे छोटे देशों की रैंकिंग में ही एक बार में इतना बड़ा सुधार आया है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कारोबार सुगमता में इतनी लंबी छलांग लगाने वाला भारत पहला देश है।

सतीश पेडणोकर

अक्टूबर 31 को विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित ''ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रिपोर्ट 2018 में 190 देशों की सूची में भारत 100वें नंबर पर पहुंच गया है। आसान कारोबार के मामले में पिछले साल भारत 130वें नंबर पर था। एक साल में देश की रैंकिंग में अभूतपूर्व 30 अंक का उछाल आया है। इतना ही नहीं, विश्व बैंक ने भारत को इस साल सबसे ज्यादा सुधार करने वाले दुनिया के शीर्ष 10 देशों की सूची में शामिल किया है। यह बात भी महत्त्वपूर्ण है कि भारत इस सूची में शामिल होने वाला दक्षिण एशिया और ब्रिक्स समूह का इकलौता देश है। विश्व बैंक के आसान कारोबार के 10 मापदंडों में से छह पर भारत की रैंकिंग में सुधार आया है। छोटे शेयरधारकों की सुरक्षा के मामले में भारत दुनियाभर में शीर्ष पांच देशों में शामिल है।

इसी तरह, आसानी से कर्ज प्राप्त करने और बिजली कनेक्शन मिलने के मामले में भारत दुनिया के 30 शीर्ष देशों में शामिल है। कहा गया है कि भारत में अब नया बिजनेस शुरू करने में सिर्फ 30 दिन लगते हैं, जबकि 15 साल पहले 127 दिन लगते थे। विश्व बैंक 15 साल से यह रैंकिंग कर रहा है। अभी तक जॉर्जिया और रवांडा जैसे छोटे देशों की रैंकिंग में ही एक बार में इतना बड़ा सुधार आया है। बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कारोबार सुगमता में इतनी लंबी छलांग लगाने वाला भारत पहला देश है। विश्व बैंक का कहना है कि भारत ने दो साल में कई बड़े कदम उठाए हैं। उनके नतीजे अब दिख रहे हैं। विश्व बैंक के मुताबिक करों का ऑनलाइन भुगतान आसान होना, एक नया कारोबारी ढांचा और भविष्य निधि और सरकारी बीमा निस्तारण के लिए लगने वाले समय में कमी भारत के प्रदर्शन में इस सुधार की सबसे बड़ी वजह हैं। विश्व बैंक की रिपोर्ट में दिवालिया कानून के प्रवर्तन का भी जिक्र किया गया है।

यह बात ध्यान देने लायक है कि ऐसी रैंकिंग नियंतग्र निवेशकों के निर्णय को प्रभावित करती है। गौरतलब है कि पिछले दिनों कारोबार को आसान बनाने के मापदंडों का मूल्यांकन करने वाले ख्यात नियंतग्र संगठन ग्लोबल रिटेल डेवलपमेंट इंडेक्स (जीआरडीआई) ने वर्ष 2017 के लिए टॉप-30 विकासशील देशों की रैंकिंग से संबंधित जो रिपोर्ट प्रकाशित की है, उसमें भारत पहले क्रम पर है और चीन का क्रम दूसरा है। यह रिपोर्ट इस दृष्टि से खास है कि इसमें न केवल उन बाजारों को शामिल किया गया है जो आज आकर्षक हैं, बल्कि भविष्य में संभावनाओं वाले बाजारों को भी स्थान दिया गया है। इस रिपोर्ट में विकासशील देशों को ग्लोबल स्तर पर खुदरा निवेश और 25 व्यापक आर्थिक व खुदरा क्षेत्र से जुड़े मसलों पर असर डालने वाले कारकों के आधार पर रैंकिंग दी गई है।

भारत के शीर्ष पर पहुंचने की जो वजह बताई गई है, उनमें उसकी तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुधार, निवेश के नियमों में ढील, कालाधन नियंतग्र के प्रयास और खपत में तेजी प्रमुख है। तेजी से बढ़ते शहरीकरण और मध्यम वर्ग के लोगों की संख्या बढ़ने और आमदनी का स्तर ऊंचा होने से देश में खपत बढ़ रही है। इसी कारण भारत का रिटेल बाजार सालाना 20 फीसद की दर से बढ़ रहा है। पिछले साल कुल बिक्री एक लाख करोड़ डॉलर यानी करीब 64.44 लाख करोड़ रुपये को पार कर गई। 2020 तक इसके दोगुना हो जाने की उम्मीद है। निश्चित रूप से पिछले तीन वर्षों में देश कारोबार में सुधार के विभिन्न मापदंडों पर क्रमश: आगे बढ़ता गया है। यदि हम पिछले तीन वर्षो के आर्थिक आंकड़ों और आर्थिक सूचकांकों को देखें तो पाते हैं कि अधिकांश आर्थिक क्षेत्रों में सफलता के कदम आगे बढ़े हैं। निश्चित रूप से सरकार आर्थिक सुधार, श्रम सुधार, बैंकिंग सुधार, कर सुधार और वित्तीय सुधार की डगर पर आगे बढ़ी है। सबसे सकारात्मक पहलू यह है कि सरकार राजकोषीय अनुशासन बनाए रखने में सफल रही है। सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा 2016-17 में घटकर 3.5 फीसद पर आ गया, जो वर्ष 2013-14 में 4.5 फीसद था।

पिछले तीन वर्षों में शेयर बाजार ऊंचाई पर पहुंचा है। रुपये में मजबूती आई है। तीन वर्ष में बेंचमार्क सूचकांक में 23 फीसद की बढ़ोतरी हुई है। विनिर्माण और कृषि क्षेत्र का बेहतर प्रदर्शन रहा है।

देश में बुनियादी ढांचे के विस्तार के लिए सरकार ने कई क्षेत्रों में 100 फीसद एफ डीआई की मंजूरी दी है। चाहे विश्व बैंक की नई कारोबार रिपोर्ट भारत के कारोबार में आसानी का परिदृश्य प्रस्तुत करते हुए दिखाई दे रही है, लेकिन अभी कई कमियों और चुनौतियों पर ध्यान दिया जाना जरूरी है। निश्चित रूप से कर अनुपालन और भुगतान किया जाना और सरल किया जाना होगा। जीएसटी का क्रियान्वयन सरल बनाया जाना होगा। कॉन्ट्रैक्ट पूरा करने और कंस्ट्रक्शन परमिट में अब भी काफी वक्त लगता है, उसे कम किया जाना होगा। कोर्ट में सुनवाई की प्रक्रिया को तेज करना होगा। प्रॉपर्टी खरीदना और इसका रजिस्ट्रेशन कराना भी आसान बनाने की जरूरत है। उद्यमियों के लिए नौकरशाही कम करने, पैसे का लेन-देन आसान करने की जरूरत है। रोजगार, निर्यात और निजी निवेश बढ़ाने के कारगर प्रयास किए जाने होंगे। कारोबार के विभिन्न कदमों को तेज करने के लिए अभी भी दिखाई दे रहे भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना होगा। चूंकि अर्थव्यवस्था में धीमापन है। अतएव आरबीआई के द्वारा ब्याज दरों में एक बड़ी आकर्षक कटौती किया जाना जरूरी है ताकि कारोबार, निवेश और देश की विकास दर में सुधार हो सके। ऐसे में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष का एवं उद्योग संगठनों का कहना है कि यदि भारत कारोबार सरलता के लिए जीएसटी के साथ विकास से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों में सुधार को आगे बढ़ाएगा, तो दो वर्षों में भारत की विकास दर आठ फीसद तक पहुंच सकती है। आशा करें कि मोदी सरकार कारोबार सुगमता के विभिन्न मापदंडों पर और तेजी से आगे बढ़ेगी और भारत विश्व बैंक की कारोबार सुगमता रैंकिंग में और ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा।

चलते चलते

दुश्मन को कमजोर न समझना

राजस्थान की सरकार ने भी उस बिल को सिर्फ प्रवर समिति को ही भेजा है, वह खत्म नहीं हो गया है, मर नहीं गया है, जिसमें सरकार की इजाजत के बिना सरकारी कर्मचारियों, विधायकों और सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार वगैरह की खबर छापने तक की मनाही की गई है। ऐसे कानून मरते नहीं हैं।

दुश्मन को कमजोर न समझने की सीख तो हमारे यहां बहुत मिलती है, पर यह सीख कहीं नहीं मिलती है कि अगर किसी काले कानून को जनता के दबाव में सरकार वापस ले लेती है तो उसे मरा मत समझिए। राजस्थान की सरकार ने भी उस बिल को सिर्फ प्रवर समिति को ही भेजा है, वह खत्म नहीं हो गया है, मर नहीं गया है, जिसमें सरकार की इजाजत के बिना सरकारी कर्मचारियों, विधायकों और सांसदों के खिलाफ भ्रष्टाचार वगैरह की खबर छापने तक की मनाही की गई है। ऐसे कानून मरते नहीं हैं। अगर वे कुछ समय के लिए शीतनिद्रा में चले जाते हैं तो लोग उन्हें मरा हुआ ही समझ लेते हैं। पर ऐसा होता नहीं है। अगर सचमुच ऐसा होता तो राजीव गांधी का प्रेस बिल राजस्थान पहुंच कर पुनर्जीवित कैसे हो जाता? यह मत समझिए कि वह कांग्रेस का था और यह भाजपा का है। अफसर की तरह कानून भी उसी का होता है, जिसका राज होता है। यूपीए की पहली सरकार में वामपंथियों ने भी यही समझा था कि भारत-अमरीकी परमाणु करार का उन्होंने विरोध किया और बस वह खत्म हो गया। पर वह खत्म नहीं हुआ था, एक दिन वह शीतनिद्रा से जागा और वामपंथियों और कांग्रेसियों के बीच आकर खड़ा हो गया। कांग्रेसियों ने कहा हम तो करार को चुनेंगे। बेकरार होकर वामपंथियों ने अपना अलग रास्ता चुन लिया। यही मोदीजी के भूमि अधिग्रहण बिल के साथ हुआ। उन्होंने तीन बार अध्यादेश जारी किया और जब विरोध नहीं रुका तो मन की बात करते-करते इसे वापस ले लिया। लेकिन वापस कहां हुआ! राज्य सरकारें दनादन भूमि अधिग्रहण कर रही हैं। केंद्र ने कहा कि हमने तुम्हें थोड़े ही रोका है।

करो। तो कुछ भी मरता नहीं है। शरीर नश्वर होता है। कानून नश्वर नहीं होता। और जिसे काला कानून कहा जाता है, वह तो कम-से-कम बिल्कुल भी नश्वर नहीं होता। वह आत्मा की तरह होता है। अपना चोला बदल लेता है। अपना रूप बदल लेता है। पुनर्जीवित हो उठता है। नया जन्म ले लेता है। दुनिया आनी-जानी है। पर कानून आना-जाना नहीं है। वह एक बार आ गया तो फिर उसका जाना बड़ा मुश्किल होता है। हमें लगता है कि वह चला गया, पर वह जाता नहीं है। घात लगाए बैठा रहता है और मौका मिलते ही अपने शिकार को दबोच लेता है।

मुद्दा

पदों की भती में गुंडागर्दी

मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में में थल सेना में सिपाही की 83 पदों की भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा के दौरान संस्कारधानी कहलाने वाला शहर अराजकता, गुंडागर्दी और लफंगई से हताश हो गया। आसपास ही नहीं दूर-दूर के आठ राज्यों कोई बीस हजार युवा जमा हुए, कुछ नाराजगी हुई, फिर पत्थरबाजी, आगजनी, लूटपाट, औरतों से छेड़छाड़। यह सब करने वाले वे लोग थे, जिनमें से कुछ को भारतीय फौज का हिस्सा बनना था। यह पहली बार नहीं हुआ है कि पिछड़े और बेरोजगारी से तंग अल्प शिक्षित हजारों युवाफौज में भर्ती होने पहुंच जाते हैं और भर्ती स्थल वाले शहर में तोड़-फोड़, हुड़दंग, तो कहीं मारापिटी, अराजकता होती है। जिस फौज पर आज भी मुल्क को भरोसा है, जिसके अनुशासन और कर्तव्यनिष्ठता की मिसाल दी जाती है, उसमें भर्ती के लिए आए युवकों द्वारा इस तरह का कोहराम मचाना, भर्ती स्थल पर लाठीचार्ज होना, जिस शहर में भर्ती हो रही हो वहां तक जाने वाली ट्रेन या बस में अराजक भीड़ होना या युवाओं का मर जाना जैसी घटनाओं का साक्षी पूरा मुल्क हर साल होता है। इसी का परिणाम है कि फौज व अर्ध सैनिक बलों में आए रोज अपने ही साथी को गोली मारने, ट्रेन में आम यात्रियों की पिटाई, दुर्व्यवहार, फर्जी मुठभेड़ करने जैसे अरोप बढ़ रहे हैं। विडम्बना यह है कि हालात दिनोंदिन खराब हो रहे हैं, इसके बावजूद थल सेना में सिपाही की भर्ती के तौर-तरीकों में कोई बदलाव नहीं आ रहा है-वही अंग्रेजों की फौज का तरीका चल रहा है-मुफलिस, विपन्न इलाकों में भीड़ जोड़ लें वह भी बगैर परिवहन, ठहरने या भोजन की सुविधा के और फिर हैरान-परेशान युवा जब बेकाबू हों तो उन पर लाठी या गोली ठोक दो। कंप्यूटर के जमाने में क्या यह मध्यकालीन बर्बरता की तरह नहीं लगता है? जिस तरह अंग्रेज देशी अनपढ़ को मरने के लिए भरती करते थे, उसी तर्ज पर छंटाई। जबकि आज फौज में सिपाही के तौर पर भर्ती के लिए आने वालों में हजारों ग्रेजुएट व व्यावसायिक शिक्षा वाले होते हैं। थल सेना में सिपाही की भर्ती के लिए सार्वजनिक विज्ञापन दे दिया जाता है कि अमुक स्थान पर पांच या सात दिन की ''भर्ती-रैली' होगी। भर्ती रैली का विज्ञापन छपते ही हजारों युवा भर्ती-स्थल पहुंचने लगते हैं। भर्ती का स्थल तय करने वाले यह विचारते ही नहीं है कि उक्त स्थान तक पहुंचने के लिए पर्याप्त सार्वजनिक परिवहन उपलब्ध भी है कि नहीं। और फिर यह तो असंभव ही है कि पचास हजार या उससे ज्यादा लोगों की भीड़ का शारीरिक परीक्षण हर दिन दस घंटे और पांच या सात दिन में ईमानदारी से किया जा सके। कहा तो यही जाता है कि इस तरह की रैलियां असल में अपने पक्षपात या गड़बड़ियों को अमली जामा पहनाने के लिए ही होती हैं। यही कारण है कि प्रत्येक भर्ती केंद्र पर पक्षपात और बेईमानी के आरोप लगते हैं, हंगामे होते हैं और फिर स्थानीय पुलिस लाठियां चटका कर ''हरी वर्दी' की लालसा रखने वालों को ''लाल' कर देती है। सेना भी इस बात से इनकार नहीं कर सकती है कि बीते दो दशक में थल सेना अफसरों की कमी तो झेल ही रही है, नये भर्ती होने वाले सिपाहियों की बड़ी संख्या अनुशासनहीन भी है।

फौज में औसतन हर साल पचास से ज्यादा आत्महत्या या सिपाही द्वारा अपने साथी या अफसर को गोली मार देने की घटनाएं साक्षी हैं शायद पहले लिखित परीक्षा तालुक या जिला स्तर पर आयोजित करना, फिर मेडिकल टेस्ट प्रत्येक जिला स्तर पर सालभर स्थानीय सरकारी जिला अस्पताल की मदद से आयोजित करना, स्कूल स्तर पर कक्षा दसवीं पास करने के बाद ही सिपाही के तौर पर भर्ती होने की इच्छा रखने वालों के लिए एनसीसी की अनिवार्यता या उनके लिए अलग से बारहवीं तक का कोर्स रखना जैसे कुछ ऐसे सामान्य उपाय हैं, जो हमारी सीमाओं के सशक्त प्रहरी थल सेना को अधिक सक्षम, अनुशासित और गौरवमयी बनाने में महत्त्वपूर्ण हो सकते हैं। सिपाही स्तर पर भर्ती के लिए कक्षा नौ के बाद अलग से कोर्स कर दिया जाए।

'बाघ बचाओ की बड़ी मुहिम

आभा स्वामी

खबर है कि गए सालों में हमारे देश में बाघों की तादाद बढ़ी है, लेकिन खबर यह भी है कि इस दौरान 0 से 6 साल की उम्र की बच्चियों की तादाद तेजी से घटी है। बाघ हमारा राष्ट्रीय पशु है और आरक्षित श्रेणी में आता है। पर उसकी खाल, हड्डी, दिल, गुर्दा सबको एशियाई बाजारों में भारी मुनाफे पर बेचा जा सकता है इसलिए पिछले सालों में लालची तस्करों द्वारा बडी तादाद में बाघों की चोरी छुपे हत्या कर अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उनके अवशेषों की कालाबाजारी से यह प्रजाति दुर्लभ हो चली थी। इसीलिए एक 'बाघ बचाओ की बड़ी मुहिम छेड़ी गई जिससे तमाम स्कूल, टीवी चैनल व एनजीओ जुड़े। उनके दबाव तथा निशानदेही से तस्करों पर छापे पड़े, पकड़-धकड़ हुई और मीडिया को जनचेतना जगाने वाले विज्ञापनों से पाट दिया गया। अब जाकर अच्छी खबर आई है कि बाघों की तादाद लगभग हर संरक्षित वन में बढ़ रही है। पर हमारी उस कन्या शिशु की प्रजाति का क्या होगा जो आज भी उपेक्षित-अरक्षित है? सबसे ज्यादा खुद मां के पेट में अपने परिवार के भीतर। परिवार के अपनों के दबाव से वह कई बार गर्भ में लिंग निर्धारण के बाद गर्भपात से, जन्म ले लिया तो गुपचुप सौरी में, और फिर भी बची रही तो लगातार उपेक्षा और कुपोषण से सुखाकर पांच की उम्र तक पहुंचने से पहले ही आज भी मारी जा रही है। नतीजतन दस साला जनगणना के जो सरकारी आंकड़े आए हैं उनके अनुसार 0 से 6 साल के आयु वर्ग में वर्ष 2001 में जहां 1000 लड़कों पर 927 बच्चियां थीं, आज सिर्फ 914 हैं। वैसे कहने को देश में औरत-मर्दों के बीच औसत लिंगानुपात में सामान्य सुधार हुआ है। लेकिन यह बात पूरी सांत्वना का विषय नहीं। पिछले दस सालों में आबादी में औरतों की तादाद बढ़ी दिखने की असल वजह यह है कि इन बरसों में कुल आबादी भी बढ़ी है। बच्चियों के क्रमश: लोप होने के असल आंकड़े तो कुल वयस्क औरतों, मर्दों के बीच आबादी में बड़े असंतुलन के रूप में तनिक आगे जाकर उजागर होंगे। यह भी चिंता का विषय है कि बच्चियों की तादाद जिन राज्यों (दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर, दादरा नगर हवेली, नगालैंड, मणिपुर तथा सिक्किम) में सबसे तेजी से घटी है, उनका स्तर आर्थिक, स्वास्थ्य कल्याण सुविधाओं और शैक्षिक पैमानों पर देश के सामान्य औसत से बेहतर है।

मात्र पिछड़े राज्यों में व्यापक गरीबी और अशिक्षा के कारण उतनी बच्चियां नहीं मर रहीं जितनी कि खाते-पीते तरक्की कर रहे राज्यों में खाते-पीते लोगों के बीच।

भ्रुण हत्या या दहेज या यौन उत्पीड़न अथवा वेश्यावृत्ति के निषेध विषयक सुधारवादी कानून भी जमीनी तौर पर अपने यहां आज भी एक किताबी कवायद ही बने हुए हैं। अगर हमारे राज-समाज में पर्याप्त आदर्शवादिता होती तो शायद सुधारवादी कानूनों का फायदा उठाकर हमारे शिक्षा संस्थान और महिला आरक्षण से लैस पंचायतें महिलाओं के महत्व को एक प्रखर राष्ट्रीय सच्चाई की शक्ल दे सकते थे। टीवी फुटेज गवाह है कि खुद त्रस्त महिलाएं जब न्याय या राशन खोजती हैं तो उनको इन तथाकथित सशक्तीकृत स्कूलों, पंचायतों, महिला थानों या सरकारी राशन की दुकान में आशा की किरण या संवेदनशीलता नहीं दिखाई देती। पर चंद शिखर नायकों के निजी हस्तक्षेप के भरोसे उन बेजुबान लड़कियों को कितने दिन बचाया जा सकता है, जिनको लेकर मदर टेरेसा ने एक बार कहा भी था कि अगर परिवार ही बच्चियों को नहीं बचाना चाहते, तो उन्हें कोई नहीं बचा सकता। क्या समाज को अपनी बेटियों की बाघों जितनी फिक्र भी नहीं होनी चाहिए?

नगर निकाय चुनाव : भाजपा की पहली सूची 4 नवम्बर को आने की संभावना

बुलंदशहर। चेयरमैन पद के प्रत्याशियों के पैनल क्षेत्रीय कार्यालय से प्रदेश कार्यालय पहुंच चुके हैं। जबकि सभासद पद के लिए नगर पालिका के क्षेत्रीय कार्यालय और नगर पंचायत के जिला स्तर से टिकट फाइनल होंगे। टिकट की लड़ाई अंतिम चरण में होने के कारण दावेदारों ने हाईकमान के यहां डेरा डाल दिया है। नगर पालिका और नगर पंचायत चुनाव में सभी की नजरें भाजपा के उम्मीदवारों की सूची पर लगी हुई हैं। भाजपाई ही नहीं विपक्षी दल भी भाजपा की सूची आने का इंतजार कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि भाजपा के चेयरमैन पद के पैनल जिला स्तर से क्षेत्रीय कार्यालय गए थे। क्षेत्रीय कार्यालय से उन्हें प्रदेश नेतृत्व के पास पहुंचा दिया गया है। सूत्रों का कहना है कि चेयरमैन के टिकट पर प्रदेश हाईकमान की मुहर लगते ही सूची जारी कर दी जाएगी। उधर, सभासद पद के लिए अभी तक दावेदारों के पैनल फाइनल नहीं हो सके हैं। जिला स्तर पर ही सभासदों को लेकर कड़ा घमासान मचा हुआ है। उधर, पार्टी सूत्र बताते हैं कि 4 नवम्बर को पहली सूची प्रत्याशियों की जारी हो सकती है। नामांकन प्रक्रिया भी 4 नवम्बर से ही प्रारंभ हो रही है। बुलंदशहर के सभासदों को लेकर हो चुकी हैं तीन बैठक नगर पालिका बुलंदशहर के 37 वार्डों के टिकट फाइनल करने के लिए अभी तक चुनाव प्रभारी और संगठन के पदाधिकारियों की तीन बैठक हो चुकी हैं, मगर अभी तक पैनल ही फाइनल नहीं हुआ। सूत्रों का कहना है कि आपसी सामजस्य नहीं बैठ पाने के कारण ऐसा हो रहा है। सूत्र बताते हैं कि हाईमान को भी इसमें दखल करना पड़ा है। अभी तक संगठन के किस-किस दायित्व को संभाला है। पहले कभी चुनाव लड़े तो क्या स्थिति रही। इसी तरह के कई सवाल पूछे। कुछ आवेदक एक साथ अंदर जाने के कारण एक-दूसरे की अंदर खामियां भी गिनाने का प्रयास करने लगे। इस पर जिला प्रभारी और निकाय चुनाव प्रभारी ने केवल अपने बारे में जानकारी देने की सख्त हिदायत दी।

चाय संग बिस्कुट खाने से 100 बच्चे बीमार, अस्पताल में भर्ती

भदोही। भदोही के कोतवाली क्षेत्र के रयां गांव स्थित पं. दीनदयाल राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय में बुधवार की देर शाम चाय संग बिस्कुट खाने से सौ से अधिक बच्चे बीमार हो गए। विद्यार्थियों को उल्टी, दस्त व पेट दर्द की शिकायत के बाद स्कूल प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए। आनन-फानन में सभी को 108 एंबुलेंस से उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों के अनुसार विद्यार्थियों में फूड प्वाइजनिंग के लक्ष्मण दिख रहे हैं, लेकिन हालत में सुधार है। उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बदहवास अभिभावक अस्पताल पहुंचे।

शहर कोतवाली क्षेत्र के रयां गांव में आश्रम पद्धति का विद्यालय संचालित है। जनपद के विभिन्न गांवों के सैकड़ों बच्चे वहां पर अध्ययन करते हैं। शिक्षा के साथ ही विद्यार्थियों को स्कूल में हॉस्टल, नाश्ता व भोजन देने की व्यवस्था है। बुधवार की शाम हॉस्टल के करीब डेढ़ सौ बच्चों को चाय के साथ खाने के लिए बिस्कुट दिया गया। इसके कुछ समय बाद उनकी तबीयत खराब होने लगी। आनन-फानन में सभी को 108 एंबुलेंस से उपचार के लिए महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल में भर्ती कराया गया।

चिकित्सकों के अनुसार विद्यार्थियों में फूड प्वाइजनिंग के लक्ष्मण दिख रहे हैं, लेकिन हालत में सुधार है। उधर, घटना की जानकारी मिलने के बाद बदहवास अभिभावक अस्पताल पहुंचे। किसी को उल्टी, तो किसी तो दस्त, जबकि अधिकांश पेट दर्द से कराहने लगे। मामले की जानकारी 108 एंबुलेंस को दी गई। आनन-फानन में सभी विद्यार्थियों को एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। उपचार के बाद उनकी तबीयत में अब सुधार है।

यूपी चुनाव:लखनऊ रैली पर आयोग की रोक, मतदान से पहले बंद होंगे मयखाने

लखनऊ। प्रदेश में नगर निकाय चुनाव की आदर्श आचार संहिता लागू होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने इस संहिता पर सख्ती से अमल की कार्रवाई शुरू कर दी है। आयोग ने कैबिनेट मंत्री और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर की पांच नवंबर को लखनऊ में प्रस्तावित रैली पर रोक लगा दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त एस.के.अग्रवाल ने बुधवार को समाचार पत्रों में रैली के बाबत प्रकाशित खबरों का संज्ञान लेते हुए लखनऊ के जिलाधिकारी से स्वयं बात की और उन्हें आचार संहिता लागू होने के बाद भी रैली की प्रशासनिक अनुमति वापस न लिए जाने पर सख्त हिदायत भी दी।

मतदान से 48 घण्टे पहले बंद हो जाएंगे सभी मयखाने:

आयोग ने आबकारी विभाग को निर्देश दिए हैं कि जिस जिले में चुनाव होगा वहां मतदान से 48 घण्टे पहले सभी लाइसेंसी देसी, अंग्रेजी शराब, बीयर व भांग की दुकानें, माडल शाप बंद करवा दी जाएं। दुकानें मतदान समाप्त होने के बाद खुलेंगी।राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने इस बाबत बुधवार को लखनऊ में आबकारी विभाग के अपर मुख्य सचिव दीपक त्रिवेदी, आबकारी आयुक्त धीरज साहू और एडीजी लॉ एण्ड आर्डर आनंद कुमार के साथ बैठक की।बैठक के बाद उन्होंने बताया कि मतगणना के एक दिन पहले रात 12 बजे से शराब, बीयर व भांग की सभी लाइसेंसी दुकानें बंद करवा दी जाएंगी और अगले दिन रात 12 बजे तक यह दुकानें बंद रहेंगी।

राज्य निर्वाचन आयुक्त एसके अग्रवाल ने बुधवार को चुनाव तैयारियों की समीक्षा की

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने सभी जिलों के अधिकारियों को निर्देश दिए कि चुनाव प्रचार खत्म होने के तत्काल बाद जिले की सभी सीमाएं सील कर दी जाएंगी। बाहर से आने वालों से पूछताछ होगी और उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जाएगी। राज्य निर्वाचन आयुक्त बुधवार को लखनऊ जोन के तहत आने वाले लखनऊ व फैजाबाद मण्डल के सभी जिलों के डीएम, एसएसपी व एसपी के साथ निकाय चुनाव को लेकर कानून-व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। समीक्षा के दौरान उन्होंने पिछले लोकसभा, विधानसभा, पंचायत और नगर निकाय के चुनावों में हुई घटनाओं और जिलों में जघन्य अपराधों व सांप्रदायिक घटनाओं में अब तक हुई कार्रवाई की जानकारी ली। आपराधिक दण्ड संहिता की धाराओं 107, 116, 109, 110जी, 122 के तहत दर्ज एफआईआर, गुण्डा एक्ट में चिन्हित अपराधियों, जिला बदर किए गए अपराधियों, लाइसेंसी जमा करवाने, लाइसेंसी की दुकानों की जांच, अवैध शराब व अवैध आग्नेया और विस्फोटक की बरामदगी के बारे में भी विचार विमर्श हुआ।

एनटीपीसी हादसा: मानवाधिकार आयोग ने उप्र सरकार को जारी किया नोटिस

लखनऊ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रायबरेली में एनटीपीसी के विद्युत संयंत्र में हुए हादसे को लेकर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार को गुरुवार को नोटिस जारी करके छह सप्ताह में जवाब मांगा।

आयोग ने रायबरेली के ऊंचाहार में स्थित एनटीपीसी के बिजली संयंत्र का बॉयलर फटने से कम से कम 28 लोगों की मौत की मीडिया रपटों का स्वत: संज्ञान लेते हुए प्रदेश के मुख्य सचिव के जरिये राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए छह सप्ताह के अंदर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। आयोग ने इस घटना पर चिंता जाहिर करते हुए माना है कि यह जीने के अधिकार से जुड़ा मामला है और इसकी फौरन उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिये, ताकि यह पता लग सके कि क्या इसके पीछे किसी तरह की लापरवाही या गलती थी। आयोग ने राज्य सरकार को निर्देश दिये हैं कि वह इस हादसे के प्रभावित लोगों को अविलम्ब सहायता मुहैया कराये।मालूम हो कि ऊंचाहार स्थित एनटीपीसी के 500 मेगावाट क्षमता वाले संयंत्र का बॉयलर कल शाम फट जाने से भारी तबाही हुई थी। इस हादसे में अब तक 28 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है।

राष्ट्रीय आपदा राहत बल (एनडीआरएफ) की टीम अब भी दुर्टनास्थल पर खोजबीन कर रही है। माना जा रहा है कि मलबे में अभी कुछ और शव दबे हो सकते हैं। प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शमार? ने बताया कि एनटीपीसी इस हादसे में मारे गये लोगों के परिजन को 20-20 लाख रुपये, गम्भीर रूप से घायल लोगों को 10-10 लाख तथा मामूली रूप से जख्मी लोगों को दो-दो लाख रुपये दिये जायेंगे।

खतरे की घंटी: चीनी किट बता रही है लड़का होगा या लड़की

लखनऊ। अब लिंग की जांच सिर्फ अल्ट्रासाउंड से ही नहीं हो रही है। खून की जांच से भी लिंग का पता लगाया जा रहा है। चीन की प्रतिबंधित किट से भारत में लिंग की जांच का खेल चल रहा है। गुपचुप तरीके से चीनी किट भारत में खपाई जा रही है। हरियाणा समेत दूसरे राज्यों में किट पकड़ी गई हैं। अप्रैल 2017 में हरियाणा और मुंबई समेत दूसरे राज्यों में चीनी किट से गर्भ में पल रहे शिशु का लिंग पता करने का घिनौना खेल चल रहा है।

सपा ने पालिका व नगर पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी घोषित किए

शाहजहांपुर। समाजवादी पार्टी ने जिले की चार नगर पालिका और छह नगर पंचायतों के लिए होने वाले अध्यक्ष पद के प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। सपा ने अधिकतर अपने पुराने ही साथियों पर भरोसा जताया है। जहां सीटें आरक्षित हो गईं, वहां निवर्तमान अध्यक्षों की पत्नी प्रत्याशी घोषित की गई हैं। नगर पंचायतों में जरूर नए प्रत्याशी उतारे गए हैं, लेकिन वह सभी पार्टी के पुराने लोग हैं। कांट में ही टिकट का बदलाव अप्रत्याशित रूप से देखा गया है। यहां निवर्तमान चेयरमैन रईस खां ने सीट आरक्षित होने के कारण अपनी मां के लिए टिकट मांगा था, लेकिन वहां पर पूर्व चेयरमैन इदरीश खां की पत्नी सुरैयाबेगम को टिकट दिया गया है।

जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने बताया कि शाहजहांपुर नगर पालिका सीट पर उनकी मां जहांआरा बेगम को अध्यक्ष पद का चुनाव लड़ाया जाएगा। इसके साथ ही तिलहर सीट से निवर्तमान चेयरमैन इमरान खां की पत्नी हाजरा बेगम प्रत्याशी होंगी। इसी प्रकार जलालाबाद में निवर्तमान चेयरमैन संजय पाठक का टिकट बरकरार रखा गया है। जलालाबाद सीट पर पूर्व ब्लाक प्रमुख के पति शकील खां ने भी अध्यक्ष पद का टिकट मांगा था, लेकिन वह सफल नहीं हो सके। पुवायां के निवर्तमान पालिका चेयरमैन संजय गुप्ता पहले ही सपा से अलग हो चुके हैं। इसलिए वहां पर इस बार गोपाल अग्निहोत्री को अध्यक्ष पद का टिकट दिया गया है।

गोपाल पूर्व सांसद मिथलेश कुमार और पूर्व विधायक शंकुतला देवी के करीबी हैं। अल्हागंज नगर पंचायत के अध्यक्ष पद का टिकट राजू शाह को दिया गया है। इसी क्रम में रोजा आरक्षित सीट पर रूकमणीदेवी सपा की प्रत्याशी होंगी। जिलाध्यक्ष तनवीर खां ने बताया कि खुदागंज से ओमेंद्र पाल सिंह, कांट से पूर्व चेयरमैन इदरीश खां की पत्नी सुरैयाबेगम, कटरा से निवर्तमान चेयरमैन सुकेश गुप्ता की पत्नी रेखा गुप्ता और खुटार नगर पंचायत के अध्यक्ष पद के लिए हरिशंकर अवस्थी को सपा ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है।

बिहार

सरकारी विभागों में ठेके या कॉन्ट्रेक्ट पर की गई भर्तियों में भी लागू होगा आरक्षण

पटना। आउटसोर्सिंग के तहत राज्य सरकार के विभागों में ली जाने वाली सेवाओं में भी आरक्षण लागू होगा। राज्य सरकार की नौकरियों की तरह इसमें भी आरक्षण के नियम लागू होंगे। राज्य कैबिनेट की बुधवार को हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में दस प्रस्तावों पर मंजूरी दी गई। बैठक के बाद कैबिनेट सचिवालय के प्रधान सचिव ब्रजेश मेहरोत्रा ने कहा कि किसी भी कार्य के लिए विभाग बाहरी एजेंसी से कर्मी की मांग करते हैं, तो उसमें यह आरक्षण लागू होगा।

किसको कितना है आरक्षण :

अनूसूचित जाति : 16, अनुसूचित जनजाति : 01, अति पिछड़ा वर्ग : 18, पिछड़ा वर्ग : 12, पिछड़ा वर्ग महिला : 03. इन सभी कोटि में 35 फीसदी महिलाओं, चार फीसदी नि:शक्त और दो फीसदी स्वतंत्रता सेनानी के पोता, पोती, नाती और नतीनी के लिए आरक्षण है। ब्रजेश महरोत्रा ने बताया कि सरकारी स्तर पर की जाने वाली बहाली में आरक्षण के जो प्रावधान लागू हैं, अब आउट सोर्सिंग के तहत प्रदान की जाने वाली सेवाओं में भी उसका पालन होगा।

उन्होंने बताया कि मंत्रिपरिषद ने 8000 नवनियुक्त सिपाहियों (महिला सहित) के प्रशिक्षण के लिए राज्य के 8 बी.एम.पी. केन्द्रों में 1000-1000 क्षमता के प्रशिक्षण केन्द्र के निमार्ण के लिए संशोधित तकनीकी अनुमोदित प्राक्किलत राशि 150 करोड 64 लाख की नयी स्कीम की प्रशासनिक स्वीकति प्रदान कर दी है। ब्रजेश ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने श्री गुरू गोबिन्द सिंह जी महाराज के 350वें प्रकाशपर्व के समापन समारोह के आयोजन के अवसर पर पटना में दो स्थानों पर अस्थायी टेंट सिटी निमार्ण के लिए 52 करोड़ रूपये के व्यय की स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 201718 में उक्त राशि को बिहार आकस्मिकता निधि से उपलब्ध कराने की मंजूरी प्रदान की गई।

गोवा में महिलाएं सेफ, दिल्ली की हालत बदतर व बिहार सबसे नीचे

नई दिल्ली। क्या आपको पता है हमारे देश में महिलाएं सबसे ज्यादा कहां सुरक्षति हैं और किस राज्य में असुरक्षति। अगर आप नहीं जानते तो आज हम आपको बताएंगे हमारे देश में कहां महिलाओं को काफी सम्मान मिलता है और वे कहां असुरक्षति हैं। इसका खुलासा कल बुधवार 1 नवंबर को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने किया। मंत्रालय की ओर से प्लान इंडिया की ओर से बनाई गई रिपोर्ट को जारी किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक, भारत में महिलाओं के लिए सबसे सुरक्षति राज्य गोवा है। इसके बाद नंबर आता है केरल, मिजोरम, सिक्किम और मणिपुर का। वहीं दूसरी ओर, जिन राज्यों में महिलाएं सबसे अधिक असुरक्षति हैं उनमें बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और देश की राजधानी दिल्ली हैं।

बिहार में 27 आईएएस समेत 55 अधिकारियों का तबादला

पटना। राज्य सरकार ने बुधवार को बड़े पैमाने पर भारतीय प्रशासनिक सेवा और बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का तबादला किया। 27 आईएएस और 28 बिप्रसे के अधिकारी बदले गए हैं। अधिकतर आईएएस अफसर जो बतौर अनुमंडल पदाधिकारी तैनात थे, उन्हें डीडीसी बनाया गया है। वहीं केन्द्रीय पदस्थापना से लौटे 2015 बैच के आईएएस अफसरों की अनुमंडल पदाधिकारी के तौर पर तैनाती की गई है। अधिसूचना के मुताबिक पूर्वी चंपारण के डीडीसी सुनील कुमार यादव को योजना एवं विकास विभाग में संयुक्त सचिव बनाया गया है। जयनगर, मधुबनी के एसडीओ राघवेन्द्र सिंह को गया का डीडीसी, बगहा के एसडीओ धर्मेन्द्र कुमार को मधुबनी, पटना सिटी के एसडीओ योगेन्द्र सिंह को पश्चिम चंपारण, आरा के एसडीओ नवदीप शुक्ला को सहरसा, बाढ़ के एसडीओ सुब्रत कुमार सेन को नालंदा, जहानाबाद के नवल किशोर चौधरी को सुपौल, पटना सदर के आनंद शर्मा को भागलपुर, मुजफ्फरपुर पश्चिमी की रंजिता को अररिया, कटिहार सदर की उदिता सिंह को रोहतास, खगड़िया सदर के अमित कुमार पाण्डेय को कटिहार, वायसी के एसडीओ शशांक शुभंकर को भोजपुर भेजा गया है। भागलपुर सदर के एसडीओ रोशन कुशवाहा को छपरा, नवगछिया के आदित्य प्रकाश को पटना, मधुबनी सदर की एसडीओ अभिलाषा कुमार शर्मा को बांका, अरवल के एसडीओ यशपाल मीणा को किशनगंज का उप विकास आयुक्त सह जिला परिषद का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी बनाया गया है। वहीं, सीवान सदर के एसडीओ श्याम बिहारी मीणा को भागलपुर और सहरसा सदर के एसडीओ सौरभ जोरवाल को बिहारशरीफ के नगर आयुक्त के पद पर पदस्थापित किया गया है।

2015 बैच के आईएएस अफसरों की हुई तैनाती

2015 बैच के आईएएस अफसर जो योगदान के पश्चात पदस्थापना की प्रतीक्षा में थे उन्हें एसडीओ के तौर पर पदस्थापित किया गया है। सीवान सदर, सुहर्ष भगत को भागलपुर सदर, घनश्याम मीणा को बगहा, प्रशांत कुमार सीएच को सहरसा सदर, सावन कुमार को वायसी, मनेश कुमार मीणा को खगड़िया सदर, सज्जन आर को बाढ़, भावेश मिश्रा को पटना सदर और जे. प्रियदर्शनी को मुजफ्फरपुर पश्चिमी का एसडीओ बनाया गया है।

बिप्रसे के अधिकारियों का तबादला

बिहार प्रशासनिक सेवा के 28 अधिकारी भी बदले गए हैं। राजेश रौशन को पटना सिटी, अरुण प्रकाश को आरा सदर, परितोष कुमार को जहानाबाद, शंकर शरण ओमी को जयनगर, किरण सिंह को अरवल, सुनील कुमार सिंह को मधुबनी सदर, नीरज कुमार को कटिहार सदर और मुकेश कुमार को नवगछिया का एसडीओ बनाया गया है। इसके अलावा बिप्रसे के कई अधिकारियों को डीडीसी बनाया गया है। इनमें कृष्णा प्रसाद गुप्ता को कैमूर, अरविंद कुमार को बक्सर, प्रभात कुमार को सीतामढ़ी, मो. वारिस खान को शिवहर, अखिलेश कुमार सिंह को पूर्वी चंपारण, डॉ. कारी प्रसाद महतो को दरभंगा, मुकेश कुमार को मधेपुरा, राम निरंजन सिंह को खगड़िया और वरुण कुमार मिश्रा को समस्तीपुर का उप विकास आयुक्त सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी नियुक्त किया जाएगा।

वहीं डीडीसी के पद पर तैनात अमरेन्द्र कुमार को संयुक्त सचिव बीपीएससी, हाशिम खां को बिहार तकनीकी कर्मचारी चयन आयोग का सचिव, मो. मोबिन अली अंसारी को अपर समाहर्ता दरभंगा, विवेकानंद झा को मुख्य महाप्रबंधक, एसएफसी, जबकि मिथिलेश कुमार को मंत्रिमंडल सचिवालय, प्रदीप कुमार को पुलिस अवर सेवा आयोग में अपर सचिव बनाया गया है।

बेतिया में थाने पर पथराव और फायरिंग, 6 पुलिस कर्मी समेत 12 घायल

बेतिया गौनाहा। गौनाहा थाने पर गुरुवार दोपहर भीड़ ने हमला कर दिया। भीड़ ने थाने पर पथराव किया और तोड़फोड़ भी की। पथराव में बलथर थानाध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह, महिला व पुरुष पुलिस समेत दर्जनभर लोग घायल हो गए। भीड़ को काबू करने के लिए आधा दर्जन थाने की पुलिस घटनास्थल पहुंची। पुलिस ने तीन राउंड फायरिंग की और लाठियां चटकाईं। इसमें कई लोगों को चोटें आईं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी विनय कुमार भी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं।

वहीं सांसद सतीश चंद्र दुबे, जिप अध्यक्ष शैलेंद्र गढ़वाल समेत कई नेता भी मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। बता दें कि लोग जेवर व्यवसायी अर्जुन सोनी (28) के हत्यारोपितों की एक महीने बाद भी हत्यारोपितों की गिरफ्तारी नहीं होने से नाराज थे। एसपी ने बताया कि गौनाहा में विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। वे खुद मामले को देखने जा रहे हैं।

इधर, गुरुवार सुबह लोगों ने पहले जमुनिया बाजार को बंद कराया और यातायात ठप कर दिया। इसके बाद आक्रोशित लोग सहोदरा थाने पहुंच गये। यहां से संतोषजनक जवाब नहीं मिलने पर लोगों की भीड़ गौनाहा थाने पहुंची। यहां गुस्साये हुए लोगों को देखते ही थानाध्यक्ष रणवीर झा ने फायरिंग कर दी। इससे लोगों का गुस्सा और भड़क गया। देखते ही देखते लोगों ने तोड़फोड़ और पथराव शुरू कर दिया। इसके बाद थानाध्यक्ष समेत सभी पुलिस कर्मी थाने से भाग गए। लोग थाने में घुस गए और खिड़की, दरवाजे व टेबलों को तोड़ दिया।

क्या है मामला :

28 सितम्बर को जेवर व्यवसायी देहात में फेरी करने निकला था। दोपहर में गौनाहा रेलवे ढाला व पंडई पुल के समीप गन्ने की खेत में खून से लथपथ व्यवसायी का शव मिला था। गौनाहा व सहोदरा थाने की पुलिस ने एक-दूसरे का इलाका होने की बात कह मामले को टाल दिया था। बाद में वरीय अधिकारियों की हस्तक्षेप के बाद गौनाहा थाने में एफआईआर दर्ज की गई। लेकिन मामले में अब तक कार्रवाई नहीं हो सकी।

मैट्रिक समकक्ष 2017 : रिजल्ट हुआ घोषित, सीवान के फिदाउल मुस्तफा बने टॉप

पटना। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड की फौकानिया परीक्षा (मैट्रिक समकक्ष) में सख्ती का असर इस बार के रिजल्ट पर साफ तौर से देखा जा रहा है। 80 हजार परीक्षार्थियों में से मात्र चार ने प्रथम श्रेणी से सफलता प्राप्त की है। मंगलवार की शाम बोर्ड के सचिव ने फौकानिया का रिजल्ट जारी किया। उन्होंने बताया कि परीक्षा केंद्रों पर सख्ती और मूल्यांकन में सीसीटीवी कैमरे से मॉनिटरिंग का नतीजा है कि प्रथम श्रेणी से पास प्रतिशत में इस हद तक गिरावट आई है। हालांकि उन्होंने कहा कि विद्यार्थियों को मायूस होने की जरूरत नहीं है। मेहनत करेंगे तो अच्छा रिजल्ट जरूर आएगा। इसबार फौकानिया में कुल 80 हजार 932 परीक्षार्थी शामिल हुए। इनमें प्रथम श्रेणी से 04 परीक्षार्थियों ने सफलता प्राप्त की। सबसे ज्यादा द्वितीय श्रेणी से पास होने का प्रतिशत रहा। इसबार कुल 32 हजार 720 परीक्षार्थी द्वितीय श्रेणी से पास हुए। वहीं तृतीय श्रेणी से 16 हजार 665 परीक्षार्थी पास हुए। फेल होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या इसबार 31 हजार 107 है। कुल पास प्रतिशत 61.79 रहा। छात्रओं की सफलता का प्रतिशत 60.56 व छात्रों की सफलता का प्रतिशत 61.03 रहा।

सीवान के फिदाउल मुस्तफा बने टॉपर : सीवान के फिदाउल मुस्तफा टॉपर रहे। पूर्णिया के मो. शहजाद सेकेंड टॉपर और नालंदा की कनीज फातिमा थर्ड टॉपर रही। इसबार फौकानिया में 31107 परीक्षार्थी रहे अनुत्तीर्ण' मदरसा बोर्ड की वेबसाइट पर देख सकते हैं ।

रिजल्ट हजार 665 परीक्षार्थी पास हुए।

दरभंगा में जहरीली चाय पीने से 4 की मौत, दो बीमार

दरभंगा । बिहार में दरभंगा जिला के पतोर थाना क्षेत्र के उघरा गांव में आज जहरीली चाय पीने से चार लोगों की मौत हो गयी तथा दो अन्य गंभीर रूप से बीमार हो गये।

बहादुरपुर के प्रखंड विकास पदाधिकारी अविनाश कुमार ने यहां बताया कि उघरा गांव निवासी राम स्वरूप महतो की पोती अर्चना ने भूलवश चाय में कीटनाशक फेराडॉल डाल दी जिससे चाय जहरीली हो गयी। बाद में परिवार के लोगों तथा पड़ोस के एक व्यक्ति ने चाय पी जिससे चार लोग अर्चना (07) ,रामस्वरूप महतो (70), प्रकाश कुमार महतो (11) वर्ष और पड़ोसी दु:खी महतो की मौके पर ही मौत हो गयी।

चुनाव विवाद में सीतामढ़ी के सांसद को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सीतामढ़ी संसदीय सीट पर हुए चुनावों में उम्मीदवार का नामांकन खारिज करने के मामले में दायर याचिका पर सांसद रामकुमार शर्मा और निर्वाचन अधिकारी को नोटिस जारी किए हैं।

मुख्य न्यायाधीश जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली तीन जजों की पीठ ने ये नोटिस उम्मीदवार रहे रामनिरंजन राय की अपील पर जारी किए हैं।

बिहार पुलिस के अधिकारी रहे राय का नामांकन यह कहकर खारिज कर दिया गया था कि वह पुलिस सेवा में हैं क्योंकि उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है। राय ने कहा कि स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के मामले में स्वीकार्यता का प्रश्न नहीं है इसे तीन माह की अवधि बीतने के बाद स्वत: स्वीकार मान लिया जाता है। इस बारे में सुप्रीम कोर्ट ने भी फैसला दिया हुआ है। लेकिन निर्वाचन अधिकारी ने उनका नामांकन खारिज कर दिया। बाद में सरकार ने 16 फरवरी 2016 को उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार कर ली।

राय ने राष्ट्रवादी चेतना पार्टी की ओर से सीतामढ़ी सीट से चुनाव के लिए नामांकन भरा था

राय ने कहा कि उन्होंने मई 2014 में हुए संसदीय चुनावों से काफी पहले 31 दिसंबर 2013 को स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के लिए सरकार को नोटिस दिया था। लेकिन सरकार ने तीन माह की अवधि बीतने के बाद भी उसे स्वीकार नहीं किया। इसके बाद अंतत: उन्होंने एसपी के पद से 1 अप्रैल 2014 को इस्तीफा दे दिया लेकिन सरकार ने उसे भी स्वीकार नहीं किया।

सूरत। परम्म पूज्य दीक्षा दानेश्वरी आचार्य श्री गुणरत्न सूरीश्वर जी म.सा., आचार्यश्री रविरत्नसूरीजी म.सा., श्री रश्मिरत्न सूरीजी के पावन सानिध्य में वाव निवासी मुमुक्षु निवासी पूजा कुमारी तथा मुमुक्षु मोक्षा कुमारी के भागवती प्रवज्या मुहुर्त के अवसर पर गुरूवार को शोभायात्रा निकाली गई। इस अवसर पर प्रात: 9 बजे प्रवचन, दोपहर 2.30 बजे देव वंदन, सायं 6.30 बजे पतिक्रमण का आयोजन ओमकार सूरी अराधना भवन, पाल में किया गया।

दुकानदार के एकाउन्ट से 98 हजार ट्रांसफर

सूरत। अडाजन के रेखा पार्क निवासी एक दुकानदार साइबर क्राइम का शिकार बना होने का मामला सामने आया है । बदमाशो ने पीड़ित के एकाउन्ट में सेंध लगाकर क्रैडिट कार्ड के माध्यम से 98 हजार ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लिए ।

सलाबतपुरा पुलिस के अनुसार अदाजन के रेखा पार्क निवासी पवन भाई पन्नालाल भंडारी 47 दुकानदार है सग्रामपुरा के आर्शीवाद एपरमेन्ट में पवन भाई की डायमंड इलेक्ट्रॉनिक नामसे मोबाइल की दुकान है । साइबर क्राइम के ठगों ने पीड़ित का आरबीएल बैंक का क्रैडिट कार्ड हैक कर 98 हजार का ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर लिए । एकाउन्ट से पैसा निकला होने का मैसेज मोबाइल फोन पर आया और पीड़ित तुरन्त बैंक में जाकर छानबीन करने पर पता चला कि उनके क्रैडिट कार्ड को हैक कर पैसे ट्रांसफर किये गए है । हादसे के चलते पीड़ित की शिकायत पर सलाबतपुरा पुलिस ने साइबर क्राइम का मामला दर्ज कर जांच शुरू की है

अथवागेट पर सड़क किनारे बने खड्डे में गिरी कार

सूरत। गुरुवार की अल सुबह एक कार मनपा द्वारा रोड पर खोदे गए गड्ढे में जा गिरी । हादसे के चलते भगदड़ मच गई। मामले की सूचना मिलते ही दमकल जवानों ने मौके पर पहुँच कर खड्डे में गिरी कार को क्रेन के माध्यम से बहार निकाला गया । हादसे में कोई जान हानि नहीं हुई है । फायर बिग्रेड के अनुसार पीने का पानी खराब आने के चलते मनपा द्वारा अथवागेट स्थित धीरज सन्स के सामने एक खड्डा खोदा गया है । गुरुवार की अल सुबह एक कार चौपाटी से अथवागेट की ओर तेज गति से जा रही कार के चालक ने स्टेरिंग पर का नियंत्रण खो दिया और कार मनपा द्वारा खोदे गए खड्डे में जा गिरी। हादसे में चालक बाल बाल बच गया। हादसे के चलते मामले की सुचना दमकल विभाग को दी गई और तुरंत दमकल जवानों ने मौके पर पहुंच कर खड्डे में गिरी कार को क्रेन के जरिये बहार निकाला गया। दमकलों द्वारा छानबीन करने पर यह कार भटार के प्रकृति अपार्टमेन्ट निवासी अमित गोर्धनभाई जालानी की बताई जा रही है।

सूरत। अमरोली में रिक्शे पर बच्चे को अगवा कर ले जा रहे गैंग को स्थानीय लोगों ने धर दबोचा तथा बच्चे को सकुशल बचा कर परिवार के हवाले कर दिया। यह बात क्षेत्र में आग की तरह फेल गई जिससे आक्रोशित लोगों ने रिक्शे में आग लगा दी। आग की सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ी घटना स्थल पर पहुंच गई और उसने आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक रिक्शा जल पुरी तरह खाक हो चुकी थी।

पीसीबी ने शराब भरी कार के साथ दो को दबोचा

सूरत। पीसीबी पुलिस को सूचना मिलने पर सचिन पलसाना रोड पर से शराब भरी कार के साथ दो जने को गिरफ्तार किया है । पुलिस ने शराब व कार सहित 3 लाख 82 हजार का मुद्दामाल जब्त किया है । वहीं एक जने को वांछित घोषित किया है ।

पीसीबी पुलिस के अनुसार स्टाफ के पुलिस कर्मियों को सूचना मिली थी कि दमण से एक कार में शराब का जखीरा भरकर सूरत आ रही है जो सचिन पलसाना रोड पर से गुजरने वाली है। सूचना के चलते पुलिस ने मौके पर पहुंच कर दबिश देकर शराब भरी कार के साथ दो जने को गिरफ्तार किया है । पुलिस ने शराब व कार सहित 3 लाख 82 हजार का मुद्दामाल जब्त किया है । वहीं एक जने को वांछित घोषित किया है । पुलिस ने दोनों आरोपियों की पूछताछ करने पर अपना नाम पांडेसरा के रविनगर निवासी पंकज हरिनाथ यादव तथा सचिन कनकपुर निवासी रोशन महेन्द्र चौधरी बताया है । पुलिस ने मौके पर से कार व शराब सहित 3 लाख 82 हजार का मुद्दामाल जब्त किया है । वहीं सचिन कनकपुर के पंकज नागेन्द्र चौधरी को वांछित घोषित किया है।

यशवंतसिंहा 14 नवंबर से तीन दिवसीय गुजरात यात्रा पर

अहमदाबाद (ईएमएस)। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केन्द्रीय मंत्री यशवंतसिंहा की गुजरात यात्रा को लेकर भाजपा की धड़कनें बढ़ गई हैं। यशवंतसिंहा जीएसटी समेत कई मुद्दों को लेकर मोदी सरकार खासकर वित्तमंत्री अरूण जेटली की आलोचना करते रहे हैं। गुजरात में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आ रहे हैं, भाजपा और कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के दौरे बढ़ गए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता यशवंतसिंह आगामी 14 नवंबर से तीन दिन की यात्रा पर गुजरात आ रहे हैं। 14 नवंबर को सिंहा अहमदाबाद में और 15 नवंबर को राजकोट में आयोजित कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। यह कार्यक्रम एक विख्यात एनजीओ की ओर से आयोजित किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस एनजीओ को कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है और सिंहा की गुजरात यात्रा से भाजपा को नुकसान तथा कांग्रेस को फायदा हो सकता है। कुछ समय पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व वित्तमंत्री पी चिदंबरम ने राजकोट में जीएसटी के मुद्दे पर राजकोट के व्यापार-उद्योगों के अग्रणियों से बातचीत की थी। अब भाजपा नेता यशवंतसिंहा अपनी गुजरात यात्रा के दौरान अहमदाबाद, राजकोट और सूरत के व्यापारियों से मुलाकात करेंगे। जानकारी के मुताबिक पी चिदंबरम की भांति यशवंतसिंहा के कार्यक्रम भी किसी राजनीतिक दल के बैनर के तले नहीं होंगे। जिसकी वजह यह बताई गई है कि यशवंतसिंहा और चिदंबरम जैसे नेता गैर राजनीतिक प्लेटफार्म पर जब बोलते हैं तो यह उनके निजी विचार प्रकट करते हैं। यशवंतसिंहा 14 नवंबर को अहमदाबाद के ठाकोरभाई देसाई होल और 15 नवंबर को राजकोट के अरविंदभाई मणियार होल में अपने विचार व्यक्त करेंगे। गौरतलब है कि हाल ही में जीएसटी की कड़ी आलोचना करते हुए यशवंतसिंहा ने कहा था कि जब हम यानि भाजपा विपक्ष में थी तब सरकार पर टेक्स टेररिजम और रेड राज का आरोप लगाती थी।

90 फीसदी ग्राम पंचायत कचहरी में शौचालय नहीं

मेहसाणा (ईएमएस)। जिले की 593 ग्राम पंचायतों में से 90 फीसदी ग्राम पंचायतों की कचहरी में शौचालय नहीं है, जिससे अपने कामों के आनेवाले लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केन्द्र की ग्रांट का उपयोग व्यक्तिगत शौचालय बनाने के बाद अब शौचालय बनवाकर देने वाली ग्राम पंचायतें ही शौचालय विहीन होने की घटना सामने आई है। मेहसाणा जिले के खुले में शौच मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है।

कैदियों को जमानत के लिए फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर देनेवाला गिरफ्तार

अहमदाबाद (ईएमएस)। जेल में बंद कैदियों को हाईकोर्ट से जमानत के लि चिकित्सा के फर्जी प्रमाण पत्र बनाकर देनेवाले शख्स को आखिरकार क्राइम ब्रांच ने गिरफ्तार कर कानूनी कार्रवाई शुरू की है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक वर्ष 2015-16 के दौरान जेल में बंद कैदियों ने हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत के लिए अर्जी की थी। इन अर्जियों के साथ कैदी या उनके परिजनों ने जिन बीमारियों का कारण दर्शाकर वीएस अस्पताल, यूएन मेहता, सिविल अस्पताल के डोक्टरों से इस उपचार संबंधी मेडिकल पुस्तिका की कापी पेश की थी। हाईकोर्ट के न्यायधीश के संज्ञान में आई इन जमानत याचिकाओं में से 97 अर्जियों के साथ पेश किए गए मेडिकल प्रमाण पत्र फर्जी होने का पता चला। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने वीएस अस्पताल, यूएन मेहता और सिविल अस्पताल के डोक्टरों का बयान कलमबद्ध किया। जिसमें इन अस्पतालों के डोक्टरों ने बताया कि मेडिकल पुस्तिका में लिखी ट्रीटमेंट उन्होंने या उनके साथी डोक्टरों ने नहीं लिखी तथा मेडिकल पुस्तिका में हस्ताक्षर भी किसी उनके या अन्य किसी डोक्टर के नहीं हैं। पुलिस ने जब कैदी और उनके परिजनों से इस फर्जीवाडे के बारे में पूछताछ की। जिसमें पता चला कि अहमदाबाद के गोमतीपुर क्षेत्र निवासी महेश शामजीभाई राठौड़ नामक शख्स ने हाईकोर्ट से जमानत के लिए फर्जी मेडिकल प्रमाण पत्र बनाकर दिए थे। महेश राठौड़ बलात्कार के मामले में साढ़े पांच महीने साबरमती सेंट्रल जेल में बंद था। उस दौरान महेश ने अन्य आरोपियों से कहा था कि उसके हाईकोर्ट के वकीलों से अच्छे संबंध हैं और उसकी ऊपर तक पहुंच है तथा वह कैदियों की अंतरिम जमानत करवा सकता है। इन अर्जियों के साथ कैदी या उनके परिजनों ने जिन बीमारियों का कारण दर्शाकर वीएस अस्पताल, यूएन मेहता, सिविल अस्पताल में उपचार संबंधी मेडिकल पुस्तिका की कापी पेश की थी। इस खुलासे के बाद क्राइम ब्रांच के अधीन एन्टी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम सेल की टीम ने सूचना के आधार पर महेश शामजीभाई राठौड़ को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू की है।

शराब छोड़ नौकरी करने की नसीहत देने पर पति ने पत्नी को मार डाला

सुरेन्द्रनगर (ईएमएस)। जिले के धमाद गांव में शराब छोड़कर नौकरी करने की पति को नसीहत देना पत्नी को भारी पड़ गई। पत्नी की नसीहत से गुस्साए पति ने उसे मौत के घाट उतार दिया। शराब समेत नशीले द्रव्यों ने अनेक परिवारों को बर्बाद करके रख दिया है, इसके बावजूद लोग सबक नहीं लेते और नशा करने से बाज नहीं आते। ऐसी ही एक घटना सुरेन्द्रनगर जिले की हलवद तहसील के धणाद गांव में सामने आई है। धणाद गांव की वाडी में रहकर खेत मजदूरी करनेवाले रमेश छगनभाई कोली को शराब की बुरी लत थी और इसकी वजह से उसने कामधंधा छोड़ दिया था। शराब पीकर रमेश कोली आए दिन अपनी पत्नी अनसुया के साथ मारपीट करता। शराब और बेरोजगारी के मुद्दे पर पति-पत्नी के बीच आए दिन छोटी-मोटी लड़ाई आम हो गई थी। इस बीच अनसुया ने शराब के नशे में आए रमेश कोली को शराब छोड़कर कामधंधा करने की नसीहत दे डाली। पत्नी की नसीहत से गुस्साए रमेश कोली ने अनसूया के सिर में लकड़ी से जोरदार प्रहार कर दिया। जिससे लहू लुहान होकर अनसुया वहीं ढेर हो गई। घटना के बाद आसपास के लोग रमेश कोली के घर पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई और अनसुया के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक अनसुया के पिता प्रभुभाई देवाभाई कोली की शिकायत पर पुलिस ने रमेश कोली के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार करने की दिशा में कवायद तेज कर दी।

182 निर्वाचन क्षेत्रों में भाजपा का गौरव संपर्क अभियान 7 से

अहमदाबाद (ईएमएस)। राज्य विधानसभा चुनाव में 150+ सीट का लक्ष्य हासिल करने के लिए गुजरात गौरव यात्रा के बाद अब भाजपा आगामी 7 नवंबर से गुजरात गौरव संपर्क अभियान चलाएगी। गत विधानसभा चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए विरोधियों को धूल चटाने वाली भाजपा अब अपने परंपरागत रास्ते पर चलना चाहती है। कांग्रेस और हार्दिक पटेल भाजपा को सोशल मीडिया अभियान पर भारी पड़ रहे हैं। जिसे देखते हुए भाजपा ने अब डोर टू डोर संपर्क का फैसला किया है। इसके अंतर्गत आगामी 7 नवंबर से 12 नवंबर के दौरान भाजपा चार दिवसीय गुजरात गौरव संपर्क अभियान चलाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अहमदाबाद के नारणपुरा क्षेत्र में गुजरात गौरव संपर्क अभियान का प्रारंभ कराएंगे। भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष व प्रवक्ता आईके जाडेजा के मुताबिक गुजरात गौरव संपर्क अभियान के दौरान राज्य के 18 2 निर्वाचन क्षेत्रों में केन्द्रीय नेता, मुख्यमंत्री, उप मख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, प्रदेश भाजपा के नेता शामिल होंगे।

भाजपा-कांग्रेस दलितों पर अपना रुख साफ करें : जिग्नेश

अहमदाबाद (ईएमएस)। ऊना कांड के बाद दलित नेता के तौर पर उभरे जिग्नेश मेवाणी ने भाजपा और कांग्रेस से दलितों के बारे में अपना रुख साफ करने की मांग की है। आज पत्रकार परिषद में जिग्नेश मेवाणी ने कहा कि गुजरात में भाजपा की दलित विरोधी मानसिकता के खिलाफ उनका संघर्ष लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि भाजपा दलितों पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है, जिससे उसके खिलाफ आंदोलन बदस्तूर जारी रहेगी। मेवाणी ने कहा कि दलितों की 17 मांगों के बारे में कांग्रेस को अपना रुख साफ करना चाहिए, उसके बाद किसी मुद्दे पर बातचीत हो सकती है। फिलहाल वे व्यक्तिगत तौर पर किसी राजनीतिक दल में शामिल नहीं होनेवाले और गुजरात के 47 लाख दलितों के अधिकारों के लिए संघर्ष जारी है। यही वजह है राजनीतिक दल के नेताओं से मुलाकात का। जिग्नेश मेवाणी ने साफ किया कि वे अब तक कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से नहीं मिले। राज्य की भाजपा सरकार को तानाशाही और अहंकारी सरकार बताते हुए कहा कि उनकी नजर में दलितों की कोई कीमत नहीं है। गुजरात में भाजपा के कारण राजनीतिक अस्पृश्यता का शिकार हैं। पिछले 22 साल से भाजपा सरकार ने दलितों को उनके अधिकारों से वंचित रखा है। गुजरात में दलितों को पांच एकड़ जमीन आवंटन करने का मामला कागजों पर सीमित रह गया है।

स्वत्वाधिकारी, मुद्रक व प्रकाशक सुरेश मौर्या द्वारा 4 ओ-ब्लाक आगम नवकार कॉम्प्लेक्ष सचीन रेल्वे स्टेश के पास,सूरत, जि. सूरत, गुजरात से प्रकाशित, एवं तासीलोक पब्लिकेशन 152,153 श्री राम इंडस्ट्रीयल एरिया पांडेसरा सूरत 394210 से मुद्रत, फोन नं. 9879141480 संपादक सुरेश मौर्या (पी आर बी एक्ट के तहत खबरों के चयन के लिए उत्तरदायी) E-mail: krantisamay@gmail.com